NEWS CLIPPING: 13.10.2018

PUNJAB KESARI

जरूरी था मैट्रो का किराया बढ़ानाः मंगू सिंह

विद्यार्थियों से रूबरू हुए डीएमआरसी के निदेशक

फरीदाबाद, 12 अक्तूबर (ब्यूरो): दिल्ली मैट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह सिंह ने कहा कि दिल्ली मैट्रो जैसी स्वयं वहनीय कोई भी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पूर्णत: सब्सिडी पर नहीं चल सकती। सब्सिडी से केवल किराये में कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है लेकिन इससे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का स्वयं वाहनीय मॉडल प्रभावित होता है।

दिल्ली और कोलकाता के मैट्रो प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रबंध निदेशक मंगू सिंह को ही श्रेय जाता है, जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विवि, वाईएमसीए में 'सतत शहरी यातायात के रूप में मैट्रो' विषय पर बोल रहे थे। सत्र की अध्यक्षता कुलपति प्रो. दिनेश कुमार ने की। कार्यक्रम को इंडस्ट्री रिलेशन्स प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किया गया था। मैट्रो किराया संशोधन को लेकर एक विद्यार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि मैट्रो का किराया आठ वर्षों के अंतराल के बाद वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था। इससे पहले यह संशोधन वर्ष 2009 में हुआ था। दिल्ली मैट्रो रेल निगम को जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, जिसने दिल्ली मैट्रो के पहले व दूसरे चरण के लिए फंडिंग की थी, का कुल 28,000 करोड रुपये का लोन चुकाना है। इस समय दिल्ली मैट्रो की अंडरग्राउंड लाइन की प्रति किलोमीटर कुल निर्माण लागत 600 से 700 करोड़ रुपये है ऊपरी लाइन की निर्माण लागत प्रति किलोमीटर 280 से 300 करोड़ रुपये है। यदि मैट्रो का किराया निरंतर अंतराल पर न बढाया जाये तो दिल्ली मैट्रो रेल निगम द्वारा लोन नहीं चुकाया जा सकता।

दिल्ली मैट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह सिंह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए।

पंजाब केसरी ई-पेपर
Sat, 13 October 2018
epaper.punjabkesari.in/c/33071822

NEWS CLIPPING: 13.10.2018

PUNJAB KESARI DELHI

सब्सिडी से नहीं चल सकती दिल्ली मैट्रो

किराया बढ़ाना जरूरी था: मंगू सिंह

- कहा . 99 प्रतिशत से ज्यादा समयबद्धता है दिल्ली मैट्रो की सफलता का राज, कैरियर में सफलता के लिए समयबद्ध रहें विद्यार्थी
- दिल्ली मैट्रो रेल निगम , डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विद्यार्थियों से हुए रूबरू

फरीदाबाद, (ब्यूरो)। दिल्ली मैट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह सिंह ने आज कहा कि दिल्ली मैट्रो जैसी स्वयं वहनीय कोई भी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पूर्णत: सब्सिडी पर नहीं चल सकती। सब्सिडी से केवल किराये में कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है लेकिन इससे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का स्वयं वाहनीय मॉडल प्रभावित होता है।

श्री मंगू जिन्होंने दिल्ली और कोलकाता के मैट्रो प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैए आज जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयए वाईएमसीए फरीदाबाद में सतत शहरी यातायात के रूप में मैट्रो विषय पर बोल रहे थे। सत्र की अध्यक्षता कुलपति प्रो दिनेश कुमार ने की। कार्यक्रम को इंडस्ट्री रिलेशन्स प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किया गया था।

मैट्रो किराया संशोधन को लेकर एक विद्यार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि मैट्रो का किराया आठ वर्षों के अंतराल के बाद वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था। इससे पहले यह संशोधन वर्ष 2009 में हुआ था। दिल्ली मैट्रो रेल निगम को जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जेआईसीए जिसने दिल्ली मैट्रो के पहले व दूसरे चरण के लिए फंडिंग की थी, का कुल 28,000 करोड़ रुपये का लोन चुकाना है। इस समय दिल्ली मैट्रो की अंडरग्राउंड लाइन की प्रति किलोमीटर कुल निर्माण लागत 600 से 700 करोड़ रुपये है और ऊपरी लाइन की निर्माण लागत प्रति किलोमीटर 280 से 300 करोड़ रुपये है। यदि मैट्रो का किराया निरंतर अंतराल पर न बढ़ाया जाये तो दिल्ली मैट्रो रेल निगम द्वारा लोन नहीं चुकाया जा सकता।

दिल्ली मैट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह सिंह संबोधित करते हुए। (छाया: पंजाब केसरी)

उन्होंने बताया कि दिल्ली मैट्रो डायनेमिक ट्रेन शेड्यूलिंग, रिजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम तथा स्टेशन की छतों पर सौर ऊर्जा जैसी नई तकनीक अपना रहा हैए जिससे बिजली की खपत कम होगी। दिल्ली मैट्रो को संचालन में दक्षता लाने के लिए नये तकनीकी सुधारों की जरूरत है।

इससे पूर्व, सत्र को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो दिनेश कुमार ने कहा कि देश की मैट्रो रेल प्रणाली की अभूतपूर्व सफलता में मंगू सिंह का योगदान महत्वपूर्ण है और वे देशभर के मैट्रो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आये है। उन्होंने कहा कि मंगू सिंह उस समय मैट्रो परियोजना से जुड़े थे, जब यह देश में बिल्कुल नई थी। किसी भी नई परियोजना का क्रियान्वयन जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि कोई भी इसकी सफलता या किये गये निवेश की वापसी का अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन जब तक कोई कोशिश नहीं करता, उसे सफलता नहीं मिल सकती और यही महत्वपूर्ण बात है जो सभी युवाओं को मंगू सिंह से सीखने की आवश्यकता है। कुलपति प्रो दिनेश कुमार ने श्री मंगू सिंह को स्मृति चिह्न भेंट किया।

सफलता के लिए समय के पाबंद रहें

मंगू सिंह, जिन्होंने दिल्ली मैट्रो के स्वच्छ विकास तंत्र अर्थात क्लीन डेवलेपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया है जो दुनिया के रेल परिवहन क्षेत्र में एकमात्र सफल प्रोजेक्ट है, ने बताया कि दिल्ली मैट्रो परिसर में सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजना के संचालन के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ दिल्ली मैट्रो ने एक समझौता किया है। समझौते के तहत दिल्ली मैट्रो रेल निगम अपने परिसर में उत्पन्न होने वाली सौर ऊर्जा को अगले 25 वर्षों तक उत्पादनकर्ता से खरीदेगा और इसके तहत निगम ऊर्जा उत्पन्न होने पर लगी वास्तविक लागत का ही भुगतान करेगा। इस समय, निगम के कुल खर्च का 38 प्रतिशत ऊर्जा संसाधनों पर खर्च होता है दिल्ली मैट्रो के प्रबंध निदेशक ने कहा कि दिल्ली मैट्रो की सफलता का सबसे बड़ा कारण समयबद्धता है। दिल्ली मैट्रो ने 99.8 प्रतिशत समयबद्धता तथा शून्य दुर्घटना रिकार्ड बरकरार रखा है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि अपने करियर में सफलता के लिए अपने जीवन में समय के प्रति पाबंध रहे।

NEWS CLIPPING: 13.10.2018

HINDUSTAN

परिवहन प्रणाली सब्सिडी से नहीं चलेगी

फरीदाबाद | वरिष्ठ संवाददाता

दिल्ली मेट्रो जैसी स्वयं संचालित कोई भी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पूरी तरह सब्सिडी पर नहीं चल सकती। सब्सिडी के माध्यम से किराये में कुछ समय के लिए राहत दी जा सकती है। इससे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का वाहनीय मॉडल प्रभावित होगा। यह कहना है दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह का।

शुक्रवार को वह जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 'सतत शहरी यातायात के रुप में मेट्रो' विषय पर एक कार्यशाला के दौरान बोल रहे थे। इसका आयोजन उद्योग संबंध (रिलेशन्स) प्रकोष्ठ की ओर से किया गया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो का किराया करीब आठ वर्षों के बाद वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था। इससे पूर्व वह संशोधन वर्ष 2009 में हुआ था। दिल्ली मेट्रो रेल निगम को जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के सहयोग से शुरू किया गया था। पहले और दूसरे चरण के लिए करीब 28 हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया गया था। उन्होंने बताया कि दिल्ली मेट्रो की भूमिगत लाइन के प्रति किलोमीटर के निर्माण पर करीब 600 से 700 करोड़ रुपये खर्च आता है। जबकि ऊपरी लाइन की निर्माण पर प्रति किलोमीटर करीब 280 से 300 करोड़ रुपये खर्च आता है।

दिल्ली मेट्रो में बिजली की खपत कम

दिल्ली मेट्रो डायनेमिक ट्रेन शेड्यूलिंग, रिजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम तथा स्टेशन की छतों पर सौर ऊर्जा जैसी आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। ताकि बिजली की खपत कम हो सके। दिल्ली मेट्रो के स्वच्छ विकास तंत्र यानी क्लीन डेवलेपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया गया है। जो दुनिया के रेल परिवहन क्षेत्र में एकमात्र सफल प्रोजेक्ट है। उन्होंने बताया कि दिल्ली मेट्रो परिसर में सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजना के संचालन के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ दिल्ली मेट्रो ने एक समझौता किया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम अपने परिसर में उत्पन्न होने वाली सौर ऊर्जा को अगले 25 वर्षों तक उत्पादनकर्ता से खरीदेगा।

NEWS CLIPPING: 13.10.2018

NAVBHARAT TIMES

हुआ सेमिनार

■ वस, फरीदाबाद : जेसी बोस विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शुक्रवार को सेमिनार हुआ। जिसमें दिल्ली मेट्रो के एमडी मंगू सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि लोन चुकाने के लिए मेट्रो का किराया बढ़ाना जरूरी था। इस मौके पर कुलपति प्रो. दिनेश कुमार, डॉ. तिलक राज, डॉ. रश्मि, डॉ. संजीव गोयल, डॉ. ज्योत्सना व डॉ. प्रीति मौजूद रहीं।

NEWS CLIPPING: 13.10.2018

AMAR UJALA

सब्सिडी से नहीं चल सकती मेट्रो किराया बढ़ाना जरूरी था: मंगू सिंह

फरीदाबाद। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह ने जेबी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सब्सिडी के बल पर मेट्रो को नहीं चलाया जा सकता है। किराया बढ़ाना जरूरी था। वाईएमसीए में सतत शहरी यातायात के रूप में मेट्रो विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता कुलपति प्रो. दिनेश कुमार ने की।

मेट्रो किराया संशोधन को लेकर एक विद्यार्थी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मंगू सिंह ने कहा कि मेट्रो का किराया आठ वर्ष बाद बढ़ाया गया। इससे पहले यह संशोधन वर्ष 2009 में हुआ था। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए), जिसने दिल्ली मेट्रो के पहले व दूसरे चरण के लिए फंडिंग की थी, का कुल 28,000 करोड़ रुपये का लोन चुकाना है। इस समय दिल्ली मेट्रो की अंडरग्राउंड लाइन की प्रति किलोमीटर कुल निर्माण लागत 600 से 700 करोड़ रुपये है और ऊपरी लाइन की निर्माण लागत प्रति किलोमीटर 280 से 300 करोड़ रुपये है। मेट्रो का किराया निरंतर अंतराल पर न बढ़ाया जाए तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा लोन नहीं चुकाया जा सकता।

वाईएमसीए यूनिवर्सिटी में संबोधित करते डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह

उन्होंने बताया कि दिल्ली मेट्रो डायनेमिक ट्रेन शेड्यूलिंग, रिजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम व स्टेशन की छतों पर सौर ऊर्जा जैसी नई तकनीक अपना रहा है, जिससे बिजली की खपत कम होगी। दिल्ली मेट्रो के संचालन में दक्षता लाने के लिए नई तकनीकी सुधारों की जरूरत है।